The House then adjourned for lunch at two minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at seven minutes past two of the dock.

The Vice-Chairman (Shri V. Narayanasamy) *In the Chair.*

CLARIFICATIONS ON STATEMENT BY MINISTER

Village Public Telephones

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Now clarifications on the statement regarding village public telephones. Shri 1sh Dutt Yadav — not here. Shri Nilotpal Basu — not here, shri Moolchand Meena. 3flq ^M $ ^tfrTCU

श्री मूलचन्द मीणा (**राजस्थान**) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मै तो वैसे भी संक्षेप में ही बोलता हूं। संचार मंत्री जी ने यह जो वक्तव्य ग्रामीण टेलीफोन के कार्यक्रम के संबंध में दिया है, उसमें कहा है कि फील्ड यूनिटों की रिपोटो की सत्यता स्वतंत्र एजेन्सी से जांच कराई जाएगी। यह अच्छी बात है, लेकिन मै माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहुंगा कि गांव में जो टेलीफोन लगे हुए है उनकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है। आप इसकी जांच कराएंगे तो पाएंगे कि ऐसे किसी भी विवाद की इतनी दयनीय स्थिति नही होगी, जितनी दयनीय स्थिति आपके टेलीफोन की है।

महोदय, मै राजस्थान के जिला सवाई माधोपुर की बात आपके सामने कहना चाहूंगा। वहां मंडराल, कर्णपुर और मासलपुर जो उप तहसील के हैडक्वार्टर है और जो एक करने टाइम के बड़े गांव है उनमे टेलीफोन की व्यवस्था वर्ष 1980 से है, लेकिन यह टेलीफोन एक तो जिस दिन लगे उस दिन चले और उसके बाद आज तक भी इन टेलीफोनों पर बात नही हुई। वह तो उप तहसील की स्थिति है। आपने गांवो के लिए वक्तव्य दिया, अच्छी बात है, लेकिन आज उप-तहसील की स्थिति यह है। जो टेलीफोन गांव में एक बार लगता है उसको और जो खराब हो जाता है उसको ठीक करने की बात तो होती ही नही है।

मै माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि गांव के अंदर जो सार्वजनिक टेलिफोन लगते है, उनकी स्थिति यह है कि जिले के जो अधिकारी है, बिना करप्शन के गांव के किसी आदमी के यहां टेलिफोन लगाते ही नही है। आज स्थिति यह है कि "सवाई माधोपुर" के "करौली" डिवीजन के अन्दर गांव के नाम पर जंगल में जो खनन का काम होता था, उन खननों पर टेलिफोन लग गए है। इसलिए मै माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप सार्वजनिक एजेंसी से जांच कराना चाहते है, कराइए, अच्छी बात है लेकिन इसके साथ ही साथ मै पूछना चाहता हूं। कि यह जांच कब तक हो जाएगी? इस जांच के क्या, किस-किस को परिणाम भुगतने पड़ेंगे यह बात आप स्पष्ट कर दे क्योकि आप यहां से, सैट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर तो कानून बना देते है लेकिन निचले स्तर पर जाकर वे कानून इम्प्लीमेंट नही हो पाते है यह बात मै आपको प्रोक्टिकल रुप में बता रहा हूं कि एक-एक टेलिफोन,जो गांव में सार्वजनिक रुप से लगता है, उस पर क्षेत्रीय अधिकारी दो-दो हजार रुपए लेता है। मै जानना चाहता हूं कि आप इसको कैसे रोक पाएंगे? गांव के प्रति आपकी जो भावनाएं है, वे बड़ी अच्छी है क्योकि आप भी ग्रामीण है, इसलिए आप उनके लिए ऐसी-ऐसी नीतियां बनना चाहते है ताकि गांव के लोगों को वास्तविक रुप में टेलिफोन मिले लेकिन अपनी नीतियों को वास्विक रुप देने के लिए क्या आपने कोई मानिटरिग सेल अलग से गांव के टेलिफोनों की जांच के लिए बनाया है और उस सेल में क्या आपने उन लोगों को, जो जनता के लोग है, जनप्रतिनिधि है, रखा है जिससे जांच वास्तविक रुप में हो सके? मै कहना चाहता हूं कि आप जिला स्तर पर डिवीजन स्तर पर जनप्रतिनिधियों की कमेटियां बनाए ताकि दूर-संचार के क्षेत्र में अगर कही कोई करप्शन हो रही हो तो उसकी जांच जनप्रतिनिधियों की एक कमेटी करे। यह आप तब करें तभी आपके वक्तव्य की मंशा पूर्ण हो पाएगी, वही मै कहना चाहता हूं।

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Mr. Chairman, Sir, I would like to know what prompted the Minister to make this statement. I do not think there is any substance in the statement. I think he was prompted by the questions we raised in the House. The scheme Village Public Telephones, was announced by Shri Rajesh Pilot. It was a unique scheme. This was done to remove the pressure on the demand for telephones. The Village Panchayat Group Telephone Scheme was a model scheme. Instead of conducting an inquiry, in both the 'a' and 'b' paragraphs of the statement, he says that he is going to ask the CBI to

investigate. We have no objection to this. Why should he waste the time of the House by making such statements? Let them ask the CBI to investigate and then come before the House With facts. We have nothing against the Government if the Government smells a scam here and there. We have seen what happened when Airbus — A-320 aircrafts were grounded. Fourteen of them were grounded for nine months. The whole country suffered a loss of Rs. 200 crores. Who was responsible for this? There is no accountability. It will not serve any purpose if we have to just make statements and entertain the gallery.

Let the Minister come to the house with facts. Let the Minister say that he had appointed the CBI to inquire into it and these were the findings and these were the people who were caught in the scam, rather than make statements which have no relevance. The scheme was wonderful. There is corruption in the Telecom Department throughout the country. Nobody can say that there is no corruption. The PCOs have been cornered by the staff and the family members of the staff of telephone exchanges. Meters are being tampered with in telephone exchanges. We made umpteen complaints. This can only be checked by the Telephone Advisor Committee. In my State, the tenure of this Committee expired in May last year. I raised this matter in the House. We also gave them a list. But nothing happened. Corruption is being compounded by this Government. When we, MPs, give theat a list, they are not bothered about it. They collect names from the streets. This is the charge made against this Govemment. So I do not know what the Minister is going to tell us by this statement-l do not find any sense in the statement. He is likely to select an institute for investigation; CBI will be asked. I do not know what the Government is trying to tell us.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Let the hon. Minister explain. The Statement does not seem to give full details. The hon. Minister can explain it in his reply.

SHRI JOHN F. FERNANDES: He is only giving information to the House that he is intending to do so and so...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): No, no what you are saying is absolutely right. The hon. Minister should have mentioned what the complaint was. Then on the basis of that complaint what action he has taken, he has to tell us. The Statement is not giving full facts.

SHRI JOHN F. FERNANDES: I presume that there was a Starred Question in this House and the House was agitated that the village telephones are not functioning because the telephones are cornered by the PCO.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): No, no, that should come in the statement itself. The details have to cone in the Statement also.

SHRI JOHN F. FERNANDES: Nothing is there, so we are just inferring it.

SHRI S.S. AHLUWALIA (Bihar): The reason was that the elder brother of Dr. Jagannath Mishra died due to nonfunctioning of telephones in Balua district.' Dr. Jagannath Mishra and I raised this issue in this House, in this session and we demanded a Statement on the village telephone system. So, that is the reason, but whatever has come is too small.

SHRI JOHN F. FERNANDES: No. Mr. Vice-Chairman, what we are saying is that most of the village telephones are not functioning because the telephones are cornered by the PCOs and their staff. That is what I am saying. So let the Minsiter come before die House with information and conduct an enquiry.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): What Mr. John F. Fernandes is saying is that if you come out with a Statement, it is all right. But what made you to come to this House with a Statment also should be narrated in this Statement. That is not there. Shri S.S. Ahluwalia.

श्री एस.एस. अहुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय,संचार मंत्री जी ने विलेज टेलिफोन के बारे में एक छोटा सा वक्तव्य दिया है। सदन जानता है कि इस बारे में वक्तव्य देने की मांग हमारे माननीय सदस्य डा. जगन्नाथ मिश्र ने की थी। कुछ दिन पहले जब बलुआ-बाजार में वहां का टेलिफोन काम नही कर रहा था, एस.टी.डी. काम नही कर रहा था, तब उनके बड़े भाई को हार्ट-अटैक हो गया था, उस समय टेलिफोन खराब होने की वजह से किसी डाक्टर से कांटेक्ट नही किया जा सका। अगर डाक्टर से कांटेक्ट हो पाता तो शायद दरभंगा से या मुजफरपुर से या पट्ना से डाक्टर भेजा जा सकता था। टेलिफोन के काम न करने के कारण पेशेंट को मरने के लिए बाध्य होना पड़ा।

महोदय,हमने सदन में मांग उठाई थी कि जैसे डेवलपमेंट के लिए और बिजनैस के लिए कम्युनिकेशन की जरूरत है,उसके साथ-साथ गांवों में भी कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन की जरूरत है क्योंकि हर गांव का बेटा कहीं फौज में है,कहीं इंडियन एयरलाइंस में हैं,कहीं पब्लिक सैक्टर में है,कहीं व्यापारी है या कहीं कुछ काम करके अपनी रोजी-रोटी कमा रहा है, उनकी सुविधा के लिए भी टेलीफोन चाहिए । वह मांग सदा से रही है और हर संचार मंत्री ने वचन दिया कि हम गांवों में टेलीफोन की सुविधा देंगे ।

महोदय,हमारा देश गांवों का देश है । एक छोटे से किसान के पास भी जब कोई खरीदार आता है या अनाज मंडी के लोग आते है अनाज खरीदने के लिए तो उसको भी सही भाव पता लगाने के लिए टेलीफोन की जरूरत है । चाहे वह साग-सब्जी हो,दूध हो या अनाज हो,इन चीजों के भाव किसान को टेलीफोन के माध्यम से पला लग सकते है । यह एक बहुत अच्छी पहल थी संचार मंत्री की,उन्होंने इस बारे में आदेश भी दिए,मीटिंग और घोषणाएं भी की परआज तक वे इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर सके ।

महोदय,जहां तक बिहार में पंचायत लेवल पर टेलीफोन लगाने की बात है,हर पंचायत का मुखिया अब तक सैकड़ों बार लिखकर दे चुका है कि हमारे इलाके में टेलीफोन लगायया जाए पर कोई सुनवाई नहीं है। केन्द्र सरकार का जो निर्देश जाता है उस पर कोई कार्यवाही नही होती। जो वहां के जी.एस. है और टेलीफोन डिपाटेमेंट के लोग है, वे इस ओर ध्यान नही देते। इंडस्ट्रियल ऐरिया में तुरंत टेलिफोन मिल जाता है लेकिन गांवो में नही मिलता। अभी एनाऊंस किया गया था कि स्वतंत्रता सेननियों को सिर्फ आवदेन पर टेलिफोन दिया जाएगा, तत्काल दिया जाएगा पर आप खुद देखिए कि कितने स्वतंत्रता सेनानी आपके पीछे घूम रहे है और उनको अभी तक टेलिफोन नही मिला है। मेरी आपसे यह भी मांग है कि आपके विभाग में यदि कोई चोरी हुई है, कोई बेईमानी हुई है तो आप उसकी निष्पक्ष खोजबीन करें और उसकी इक्वायरी कराएं।

सी.बी. आई. से इंक्वायरी कराएं। सी.बी. आई. के ऊपर कोई और हो तो उससे भी करालें। क्योकि हम नही चाहते कि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होकर हमारे देश का पैसा जो जनता के उपयोग का है उस पैसे का दोहन करके वह अपनी सम्पति को बढ़ाए। यह राष्ट्र की सम्पति है और राष्ट्र की सम्पति की रक्षा करना हमारा फर्ज है और उस फर्ज को निभाते हुए अगर कोई कार्रवाई करते है तो हमारा पूरा समर्थन है आपको। परन्तु मेरी मांग सिर्फ इतनी है कि पंचायत लेविल पर टेलिफोन देने का जो वायद संचार मंत्रियो का है, वह कब तक पूरा कर देंग़े यह बताने की कृपा करें? खासकर के बिहार में पंचायत लेविल में भी मै आपसी कहूंगा कि कटाव क्षेत्र को पकड़िए पहले। गंगा के किनारे-किनारे गंड्क के किनारे-किनारे महानदी के किनारे-किनारे और जो कटाव क्षेत्र में लोग रहते है और दूरदराज में कोई रास्ता नही है। दूसरी बात, जहां-जहां आपके पोस्ट आफिसेज है, सब-पोस्ट आफिसेज पर एक-एक पी.सी.ओ. की व्यवस्था कब तक हो जाएगी, वह बताने की कृपा करें? हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है जिसको आपने कनेक्शन देने का वायदा दिया हुआ है, वह कब तक पूरा कर देगें?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Now, Shri Thalavai Sundaram. Mr. Sundarara, please be brief. Please conclude within two minutes.

SHRI N. THALAVAI SUNDARAM (Tamil Nadu): Mr. chairman, Sir, I belong to Thovali village in Kanyakumari district of Tamil Nadu. Last week I went to my village and I wanted to contact somebody. But I was told that my telephone was out of order for more than one week. As far has telephones in villages

are concerned, they are the main, vital links with outside world. Unfortunately, most of the village telephones either in hospitals or schools or anywhere are not properly working. The Department people don't attend to telephone complaints. It is particularly so in Kanyakumari district. They never attend to telephone complaints immediately. The Minister said in his statement that he would order a CBI probe. But the CBI people would not come to villages. They sit in the headquarters. They never come to the village areas.

I think a Committee comprising Lok Sabha and Rajya Sabha Members as also the concerned Panchayat Presidents to see whether the village telephones are functioning properly. Secondly, the Minister should clarify as to what exactly is the application fee for telephones in different places because the fee varies from Rs. l.OOfy- to Rs. *3,(W-* depending upon the area. Unless local Committees are cosntituted nominating the concerned MPs and the Panchayat Presidents to investigate into the functioning of the village telephones, there is no use blaming the Central Governemnt or the CBI. All of the must co-operate so as to see that communkaiton system in the villages is strengthened. If there are no dependable telephones in the villages, we will not be able to attend to our works, whether it is a marriage, political work or any emergency. I request the hon. Minister to take necessary action, particularly in regard to the problems of Kanyakumari district.

Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Shri Jalaludin Ansari. Mr. Ansari, please confine yourself to the Minister's statement because most of the Members are not doing so. You must also be very brief.

श्री जलालुदीन अंसारी (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, संचार मंत्री जी ने जो अपने बयान में यह मंशा दिखालाई है कि ग्रामीण सार्वजनिक टेलिफोन में जो गढबढी हुई उसकी जांच किसी एजेसी से कराना चाहते है। मै उनसे कहना चाहूंगा कि उस एजेसी को आप तय कीजिए और सदन को बताइए कि किस एजेसी से जांच कराना चाहते है। वह प्रशासनिक स्टाफ कालेज हैदराबाद हो या कोई फिर दूसरी एजेसी हो। आपके बयान के दूसरे पैरा में कहा गया है कि-सी.बी. आई. को कहा जाएगा। इसका मतलब है कि अभी निश्चित नही किया गया है कि किस एजेसी से जांच कराएंगे। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि इस गड़बढी की जांच के लिए आप कोई एजेंसी तय करें और उससे हम लोगों को भी अवगत कराएं। यह सर्विविदित है कि ...(**व्यवधान**)...

उन्होंने कहा है कि कहा जाएगा। इसका मतलब है कि निश्चित नही है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. VRAYANASAMY): Let him clarify that.

श्री जलालुदीन अंसारी : मेरा कहना है कि जिस एजेसी से भी हो स्पष्ट करें कि वह किस एजेसी से कराने जा रहे है। अभी निश्चित नही है। मै चाहता हूं कि निश्चित हो जाए कि किस एजेसीं के द्वारा जांच होगी? यह सही है कि हमारे बिहार के गांवो में टावर के जरिए टेलिफोन कब लगेगें? पंचायत के सामुदायिक भवन में, पंचायत भवन में या पोस्ट आफिस में टेलिफोन कनेक्शन नही मिल पा रहे है, यह हमारे साथी अहलुवालिया जी ने भी कहा। मै भी बिहार को बिलांग करता हूं और बिहार में इस की आम तौर पर कठिनाई है। इसी तरह की स्थिति दूसरे राज्यों में भी होगी। तो मै माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आपने जो टेलिफोन देने का वायदा किया है उसको लागू करने के लिए कार्यवाही कीजिए और इसकी जांच अवश्य कराइए। गया जैसे शहर में कभी-कभी चार सौ-पांच सौ टेलिफोन डेड हो जाते है और महीनो डेड रहते है। गया एक प्रमंड्ल है, कमिशरी है। मेरा टेलिफोन भी दो महीने तक बंद रहा तो इनके विभाग में भी गड़बढी है। ढाई सौ-तीन सौ टेलिफोन हमेशा ही खराब रहते है। मै गया में रहता हूं इसलिए मै आपसे कह रहा हूं कि आप इसे देखिए। गया की एक इंपोटिस है, महत्व है, सभी लोग इसको जानते है। दूसरे पिछले दो-तीन महीनों से बिल इतना ज्यादा आ रहा है कि पता ही नही चलता कि इतने टेलिफोन कब किए गए? मै तो टेलिफोन पर लॉक भी लगा कर रखता हूं।

کھڑا ہے اور لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اس ٹاور کے ذریعے ٹیلیفون کب لگینگے؟ پنچایت کے سمودایک بھون میں، پنچایت بھون میں یا پوسٹ آفس میں ٹیلیفون کنیکشن نہیں مل پا رہا ہے ہیں۔ اور بہار میں اس کی عام تور پر کٹھینائی ہے۔ اسی طرح کی استتھی دوسرے راجیوں میں بھی ہوگی۔ تو میں مانننیئے منتری مہودے جی سے کہنا چاہونگا کی آپنے جو ٹیلیفون دینے کا وعدہ کیا ہے، اسکو لاگوں کرنے کے لئے کاروائی کیجئے اور اسکی چانچ صرور کرائیے۔ گیا جیسے شہر میں کبھی کبھی چار سو۔پانچ سو ٹیلیفون ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور مہینو ڈیڈ رہتے ہیں۔ گیا ایک پرمنڈل ہے، کمیشنری ہے۔ میرا ٹیلی فون بھی دو مہینے تک بند رہا تو انکے وبھاگ میں بھی گڑبڑی ہے۔ ڈھائی سوتین سو ٹیلیفون ہمیشہ ہی خراب رہتے ہیں۔ میں گیا میں رہتا ہوں اسلئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کی آپ ا سے دیکھئے۔ گیا کی ایک امپورٹینس ہے، مہتو ہے، سبھی لوگ اسکو جانتے ہیں۔ دوسرے، پچھلے دو-تین مہینوں سے بل اتنا زیادہ آ رہا ہے کی پتہ ہی نہیں چلتا کی اتنے ٹیلیفون کب کے گئے؟ میں تو ٹیلیفون پر لاک بھی لگاکر رکھتا ہوں۔

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Aauriji, we will

†**شری جلال الدین انصاری "بہار"**: اپ سبھا ادھیکش مہودے، سنچار منتری جی نے جو اپنے بیان میں یہ منشا دیکھلائی ہے کہ گرامیڑ ساروجنک ٹیلی فون میں جوگڑبڑی ہوئی اسکی چانچ کسی ایجنسی سے کرنا چاہتے ہیں۔ میں انسے کہنا چاہتا ہوں کہ اس ایجنسی کو آپ طے کر دیجئے اور سدن کو بتایئے کہ کس ایجنسی سے چانچ کرانا چاہتے ہیں۔ وہ پرشاسنک اسٹاف کالج حیدرآباد ہو یا کوئی پھر دوسری ایجنسی ہو۔ آپکے بیان کے دوسرے پیرا میں کہا گیا ہے کی۔ سی۔بی۔آئی۔ کو کہا جائیگا۔ اسکا متلب ہے کی ابھی نشچت نہیں کیا گیا ہے کہ کس ایجنسی سے جانچ کرائینگے۔ میرا آپ سے یہ پرشن ہے کی اس گڑبڑی کی جانچ کے لئے آپ کوئی ایجنسی طے کریں اور اس سے ہم لوگوں کو بھی اوگت کرائیے۔ یہ سرودت ہے کہ..."مداخلت"...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Let him clarify that.

†**شری جلال الدین انصاری:** میرا کہنا ہے کہ جس ایجنسی سے بھی ہوا اسپشٹ کریں کہ وہ کس ایجنسی سے کرانے جا رہے ہیں۔ ابھی نشچت نہیں ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ نشچت ہو جائے کہ کس ایجنسی کے ذریعے جانچ ہوگی یہ صحیح کہ ہمارے بہار کے گاؤں میں ٹاور

† [ ] Transliteration in Arabic Ser

discuss it on a later date. You seek clarifications on the statement.

श्री जलालुदीन अंसारी : तो इसलिए यह जो गड़बढी है, इसको ध्यान में रखते हुए आप यह जांच कराए एजेसी तय करें और सदन को बताए क्योकि जांच होनी आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों मे टेलिफोन देने का इनका जो वायदा है, उसे वे पूरा करें, इतना ही मुझे कहना है।

†**شری جلال الدین انصاری:** تو اسلئے یہ جوگڑبڑی ہے، اسکو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ یہ جانچ کرائیں، ایجنسی طے کریں اور سدن کو بتائیں کیونکے چانچ ہونی ضروری ہے۔ گرامین چھیتروں میں ٹیلیفون دینے کا انکا جو وعدہ ہے، ا سے وہ پوراکریں، اتنا ہی مجھے کہنا ہے۔

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Shri Nilotpal Basu. You were not there when your name was called.

SHRI NILOTPAL BASU: I am sorry, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Please be brief and ask only pointed questions.

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Sir, firstly, I thank the Minister for having responded promptly to the issues that had come up in the House. Now, the inquiry will be in two parts. Of course, I do not understand what the intention is. Anyway, one part of the inquiry will be dealt with by some technical agencies like the Administrative Staff College, Hyderabad or one of the Indian Institutes of Management. The other part is, if any criminal aspect is involved, it will be inquired into by the CBI. there are two things. Of course, the problem is there at both the levels. We have discussed at length the criminal aspects of it. Earlier some cases had also come up and on the basis of that the CBI had taken up certain cases. Certain firms which were dealing with this particular equipment —MAAR and other systems — had been indicated, charge-sheeted and so on and so forth. The second part relates to the policy decisions that were taken and on the basis of which there might have arisen certain problems.

My feeling is that this decision of the Govemment should have come a bit earlier. Why was this decision on conducting an inquiry not taken earlier? It was very clear that there had been large scale corruption, particularly in terms of equipment that was necessary for installation of village public telephones. The Minister himself has gone on record to say in this House that in the last three years so far as targets pertaining to installation of village telephones arc concerned, the DOT, notwithstanding its good performance in some sectors, has failed to achieve the targets.

The targets were affected. So, I would like to know whether that process led to shortfall in achievement of targets. Normally, one would expect that that v/ould have affected the quality of service also. So, I would like to know as to why surh an inquiry was not conducted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Okay.

SHRI NILOTPAL BASU: Then, there is another point...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): At 2.30, we have to start the Private Member's Business.

SHRI NILOTPAL BASU: I want to know as to which agency will also go into the kind of tendering and other things which were there and the quality of equipment which were taken. Continuously, in the last three-four years, the price had been falling and we were given to understand that the price fall was not always natural. It was artificial. .^*interruptions)*... Apparently, the price advantage which the DOT was showing

† [ ] Transliteration in Arabic Script.

whether that had actually been reflected in terms of quality of equipment supplied which had resulted in such a situation. So, the hon. Minister may kindly clarify all these points.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Now it is 2.30 and we have to take up the Private Members' Business. If the House so agrees, we can take ten more minutes to enable vhe Minister to reply. Then, we will take up the Private Members' Business. If the House so desires, we will adjust that time later

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Shri Sanatan Bisi. There is only one minute for you. After that, the Minister will reply.

SHRI SANATAN BISI (Orissa): Sir, so far as the second part of the statement is concerned, our Government is very transparent and accountable. I would like that the Minister should set some deadline by which the CBI inquiry will be conducted. I would also like that the report of the CBI inquiry should be laid on the Table of the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Hon. Minister of Communications

संचार मंत्री (श्री वेनी प्रसाद वर्मा) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी राय दी है, उससे निश्चित्त रुप से जो सरकार का लक्ष्य है, उसको पूरा करने में मदद मिलेगी इसलिए मै सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करता हूं। इस मंत्रालय का कार्यभार संभालने के तुरन्त बाद क्योकि मै भी उसी पृष्ठभूमि का ही हूं सबसे ज्यादा ध्यान हमारा ग्रामीण सार्वजनिक टेलिफोन की ओर गया है और यह कहने में मुझे कोई संकोच नही है कि ग्रामीण सार्वजनिक टेलिफोन का कार्य इस विभाग में उपेक्षित ही रहा है। पिछले कई वर्षो में लक्ष्य का 50 प्रतिशत कार्य भी पूरा नही हुआ है। इसलिए प्रारम्भ में ही हमने इसके लिए अलग से बजट एलोकेशन किया था और इसके लिए मनिटरिग सैल भी बनाया गया था। जैसा हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने जानने का प्रयास किया था, हमने

पहले ही मानिटरिग सैल बना दिया था और इस वीकली उसकी रिपोर्ट मंगा रहे थे। अब यह वर्ष समाप्त होने को है लेकिन जिस तरह से हमारे माननीय सदस्यागण असंतोष व्यक्त कर रहे है, करीब-करीब हम भी उन्ही से स्वयं को संबद्ध करते है क्योकि हम भी इससे पूरी तरह से संतुष्ट नही है। हमको यह फैसला लेना पड़ा क्योकि ग्रामीण सार्वजनिक टेलिफोन की उपयोगिता आज बढती जा रही है, जैसा हमारे माननीय सदस्य श्री अहलुवालिया जी भी कह रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए इसकी उपयोगिता दिन-पर-दिन बढ रही है। क्यों ऐसा हुआ? जब हमने यह चीजे इन्ट्रडयूस की तो शुरु के सारे इस्टूमेट फेल कर गये। क्यों फेल कर गये? इसकी जांच बहुत पहले होनी चाहिए थी। तो यह हमारी जानकारी में आया और जो ज्वाइंट पार्लियामेटरी कमेटी है,उसने भी इस बात को नोटिस किया इसलिए हमने कल निर्णय किया। ग्रामीण सार्वजनिक टेलिफोन के कार्यकरण के बारे में फील्ड यूनिटे जो हमें रिपोर्ट भेज रही है, उससे हम पूरी तरह संतुष्ट नही थे क्योकि हमको रिपोर्ट भेजी गयी थी कि 70 प्रतिशत इंस्टूमेट काम कर रहे है और जो फीड बैक मिल रहा है, उससे पूरी तरह हम संतुष्ट नही थे। उस विभाग से ही अगर जांच करवाई जाती तो उस पर फिर प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो सकता था इसलिए हमने निर्णय किया कि इसकी सत्यता को प्रमाणीत करने के लिए स्वतंत्र एजेसी से इसकी जांच करवा ली जाए लेकिन साथ ही साथ हमने यह इंस्ट्रक्शस भी दे दी है कि जो लक्ष्य है, उसको पूरा करने में जांच की वजह से दिक्त नही आनी चाहिए और लक्ष्य पूरा हो, ग्रामीण सार्वजनिक टेलिफोन लगाने के काम में और तेजी आए और वह काम भी चलता रहे और इसकी सत्यता को प्रामणित करने के लिए एजेसी के द्वारा अलग से जाच होती रहे।

हमारे असारी साहब ने अभी कहा था कि सीबीआई को कहा जाएगा यह एक आश्रासन है और सरकार यह कहने के बाद मुकर नही सकती है। कुछ फारमल्टीय़ है वह पूरी करनी पड़ती है, वह हो रही है और जल्दी होगी। वह इस बात की जांच करेगी कि शुरु में जो एम एआर आर या दूसरे इस्टरुअमेट क्यो फेल हो गये उनमे कौन-सी टेकीकल खराबी थी, कोई फाइनेन्सियल उससे इरेगुलरिटी हुई थी कि नही हुई थी, कोई लीगल इरेगुलरिटी हुई थी कि नही हुई थी और जब से एम एआर आर इट्रोड्यूस हुआ है त्तब से अब तक कि फाइनेशियल टेकिकल या और भी उसमें कोई इरेगुलरिटी अनियमितता है तो उसकी जांच सीबी आई

करेगी और उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। सुधार तो एक निरन्तर प्रकिया है। मै समझता हूं कि इससे इस दिशा में थोड़ा सुधार भी आयेगा।

महोदय, हम उससें और भी कुछ सुधार करना चाहते है उसकी भी मै यहा स्प्ष्ट कर देना चाहूगा। उस पर हम अभी विचार कर रहे है और आप लोगों की राय होगी तो उस पर निर्ण्य लेगें। हम खासतौर से ग्रामीण टेलिफोन के बारे में सुधार करना चाहते है। जिलों को और जिले के अधिकरियों को इसमें शामिल किया जाएगा। माननीय सद्स्यों को भी हमारे चिभाग के अधिकारी सूचित करेंगे कि इतने टेलिफोन ठीक है और इतने खराब है जिससे माननीय सद्स्यों को यह जानकारी रहेगी कि वह ठीक बता रहे है। अगर ये किसी गांव में जाये और टेलिफोन ठीक बता रहे है। अगर ये किसी गांव में जाये और टेलिफोन ठीक न हो तो उनसे कंप्लेट कर सके। इस तरह की इंस्ट्रकशंस हम जारी करने जा रहे है। यह जो सार्वजनिक ग्रामीण टेलिफोन में सुधार लाने के लिए कार्रवाई की जा रही है उसमें विभिन्न निर्माताओं की मदद से खराब पड़े एमएआर आर के उपकरणों की मरम्मत करना अनुरक्षण रहित बेटरियों का इस्तेमाल करना आदि। एक नई बैटरी आ गई है जिसमें मेटीनेस करने की जरुरत नही पड़ती है, उसमें डिस्टल्ड वाटर नही डालना पड़ता है, वह इंट्रोडयूस की जा रही है। ग्रामीण सार्वजनिक टेलिफोन की मरम्मत के लिए पिछले चार महीने के दौरान एक विशेष अभियान चलाना गया है लेकिन पूरी तरह से संतुष्ट नही होने के कारण हमको यह कदम उठाना पड़ा है। ग्रामीण सार्वजनिक टेलिफोन के कार्यकरण की मानीटरिग करने में राज्य सरकारों का सहयोग लेने का प्रस्ताव है। जैसा मैंने पहले कहा कि स्वतंत्र एजेन्सी की रिपोर्ट की जानकारी हमको तो मिलेगी ही लेकिन साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट और हमारे ड्पार्टमेंट के लोग माननीय सदस्यों से सम्पर्क करेंगे जिससे हमें एक अलग फीड बैक मिलेगा कि वे काम कर रहे है या नही कर रहे है और स्वतंत्र एजेन्सी अपना अलग से कार्य करेगी। विशेषरुप से हमको जो यह निर्णय लेना पड़ा वह इसी वजह से लेना पड़ा कि जो अपेक्षाएं ग्रामीण लोगों की, जनप्रतिनिधियों की थी, उन अपेक्षाओं को पूरी तह से हम कह सकते है कि पूरा नही किया जा रहा है। इसलिए यह आवश्यक था कि जो कार्य है उसमें किसी प्रकार की वाधां पहुंचाए बिना लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पूरी मेहनत करते हुए इन चीजों की भी एक स्वतंत्र एजेन्सी जो हमको रिपोर्ट देगी उसमें भी हमने तीन चीजों को खासतौर से रखा है। पहला है कि कार्य कर रहे ग्रामीण सावर्जनकि टेलीफोन की संख्या का सत्यापन करना। दूसरा मानीटरिग और रिपोर्टग प्रकिया संबंधी सुझाव देना और तीसरा स्थनो और अन्य पैरा मीटरों में नीति संबंधी परिवर्तनों का सुझाव देना। उस एजेन्सी से हम यह भी कहेंगे कि इन तीन पैरा मीटर्स के बारे में भी हमको अपनी राय दे। इसी के साथ-साथ सीबीआई जांच करेगी इसके बारे में हमने पहले संक्षपे में बता दिया है। एम एआर आर उपकरणो के घटिया काम करने और कुछ ऐसे उपकरण जिनकी मरम्मत संभव नही है ऐसे उपकरण क्यो खरीदे गये, इसके बारे में सीबीआई जांच करेगी।

संचार स्थायी संसदीय समिति में एम एआर आर के बारे में प्रश्न उठाया गया था और संसदीय समिति की भी यह अपेक्षा थी कि इसमें जांच कराई जाये। इन सभी कारणों से और ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधाओं की आवश्यकताओं को देखते हुए सिर्फ वहां पर टावर न खड़े कर दिये जायें वे टावर काम भी करें इसलिए निर्णय लेना पड़ा है। मै समझता हूंकि इस निर्णय से ...ग्रामीण क्षेत्रो में संचार सुविधाएं पहुंचाने का विभाग का लक्ष्य है उसमें जो कुछ दिकते आ रही थी इससे कुछ मदद मिलेगी। हमारे जनप्रतिनिधियों का भी इसमें सहयोग बढेगा और एक पारदर्शिता भी बढेगी और जो हम सब लोगों की ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति जिम्मेदारी है उसको भी हम पूरा कर पायेंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Hon. Minister, I would like to observe that while discussing this issue, hon. Members made certain complaints with regard to the functioning of telephones. You please take care of this aspect. Secondly, while making a statement like this, you should also mention the background on the basis of which it emanates. This is missing in the present statement. Please take note of it also. ...*(Interruptions)*...

SHRI JOHN F. FERNANDES: Sir, what about the report of the Inquiry Committee? ... *(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): The Minister may take his own decision in this regard. I cannot force him.